



## भारतीय अनुसूचित जनजाति के गरीबी की स्थिति और परिणाम

मंगल नागोराव मारकड<sup>1</sup> & जे. एस. भोयर<sup>2</sup>, Ph. D.

<sup>1</sup>संशोधक विद्यार्थी-नी स्वा. रा. ती. म. विद्यापीठ, नांदेड.

<sup>2</sup>प्राचार्य कै. बाबुराव पाटील कला विज्ञान महाविद्यालय, हिंगोली



*Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at [www.srjis.com](http://www.srjis.com)*

### प्रस्तावना

भारतीय समाज व्यवस्था में आदिवासी समाज यह बहुत महत्वपूर्ण घटक है। इस आदिवासी समाज में लगभग 414 जनजाति है। और यह सभी जनजाति संपूर्ण भारत में बड़ी संख्या में फैले है। इस अनुसूचित जनजाति को अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है। Aboriginal या Aboriginels इसका मतलब मूल निवासी, प्राचीन या आदिवासी ऐसे कहा जाता है। यह प्राचीन आदिवासी समाज बड़े पैमाने में जंगल, खाई, पर्वत और पहाडों में प्राचीन काल से ही रहते है। इस वजह से आदिवासी समाज के सामने अनेक समस्याएँ है। इन समस्याओं में एक महत्वपूर्ण समस्या है। गरीबी। ऐसे गरीबी में फसे हुए आदिवासी समाज की समस्या को सुलझाने के लिए योजना काल से ही अनेक उपाय योजना किए गए है। आर्थिक योजना को स्विकार किए 62 साल से अधिक समय होने के बाद भी भारत में 29 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या बेरोजगारी, कुपोषण, निरक्षरता, आर्थिक विषमता, आर्थिक वृद्धि दर में धीमी, शहरीकरण का धीमी गती से विकास इस वजह से बेरोजगारी का प्रतिशत बढ़ गया है। गरीबी के बारे में आनंद तेलतुबडे कहते है। *Poverty is cencer of economy* इसे गरीबी की समस्या का कितना भीषण रूप है। इसका पता चलता है। गरीबी उन्मूलन के माध्यम से इस समस्या पर मात करने की कोशिश की गई है।

गरीबी पर विचार करते हुए नई सत्ता पर आए सरकारने दिए गए वचनो में प्रधान मुद्रा के रूप में अग्रक्रम दिया गया है। अर्थ संकल्प 2014 - 15, 2015 - 16 में इन वचनो का रुपांतर अर्थ संकल्प के प्रस्ताव के रूप में की कोशिश की गई है। वैसे ही गरीबी को कम करके कुपोषण का सामना करते हुए सरकारने स्वतंत्रता के बाद के समय में बहुत बड़े पैमाने में कार्यक्रम योजना को साकार किया है। उनमें से आदिवासी उपयोजना, एकीकृत बालविकास सेवा योजना (ICDS) जैसी योजना चार दशक से पहिले ही शुरू की गई है। सभी को काम का हक्क आधारित मनरेगा जैसी और योजनाओं का निर्माण गरीबी उन्मूलन करने के लिए किया गया है।

### संशोधन के उद्देश

1. गरीबी की संकल्पना को स्पष्ट करना ।
2. भारतीय अनुसूचित जनजाति के गरीबी की स्थिति का अध्ययन करना ।

3. अनुसूचित जनजाति के गरीबी की स्थिति के परिणामों का अध्ययन करना।

### संशोधन पद्धति

इस शोध निबंध में दुय्यम सामग्री का उपयोग किया गया है। जिस में मुख्य तोर पर संदर्भ ग्रंथ, मासिक, नियत कालिक, सरकार के विभिन्न अहवाल और वेबसाईड के उपयुक्त आकड़ों का आधार लिया है।

### गरीबी का अभिप्राय

गरीबी का अर्थ जिसमें समाज का कुछ भाग अपने जीवन में आधारभूत आवश्यकताओं को (भोजन, कपडा, स्वास्थ्य आवास) पूर्ति करने में असमर्थ हो।

गरीबी की संकल्पना निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी दो अर्थों से लागू जाते हैं।

#### 1) निरपेक्ष गरीबी (Absolute Poverty)

जब मणूष्य आपनी और अपने परिवार की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति उसे अपने मिलनेवाली आय से करने में असमर्थ हो तो उसे निरपेक्ष गरीबी कहते हैं।

#### 2) सापेक्ष (Relative Poverty)

जब जनसंख्या को आय के अनुसार विभिन्न श्रेणी या वर्गों में बाटा जाता है। तो उची आय वाले लोगों अधिक संपन्न होते हैं। और कम आय वाले गरीब होते हैं। तो कम आय वाले व्यक्ति उंची आय वालों की तुलना में गरीब होते हैं।

इस तरह सापेक्ष गरीबी का अभिप्राय असमानता से है। सापेक्ष गरीबी आर्थिक असमानता श्रेणीय असमानता अथवा अन्तर्राष्ट्रीय असमानताओं का बोध कराती है।

### गरीबी रेखा (Poverty Line)

यूनतम आय का वह स्तर जो औसत आकार के परिवार के जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुओं को खरीदने की क्षमता रखता है।

### गरीबी रेखा के मापदंड

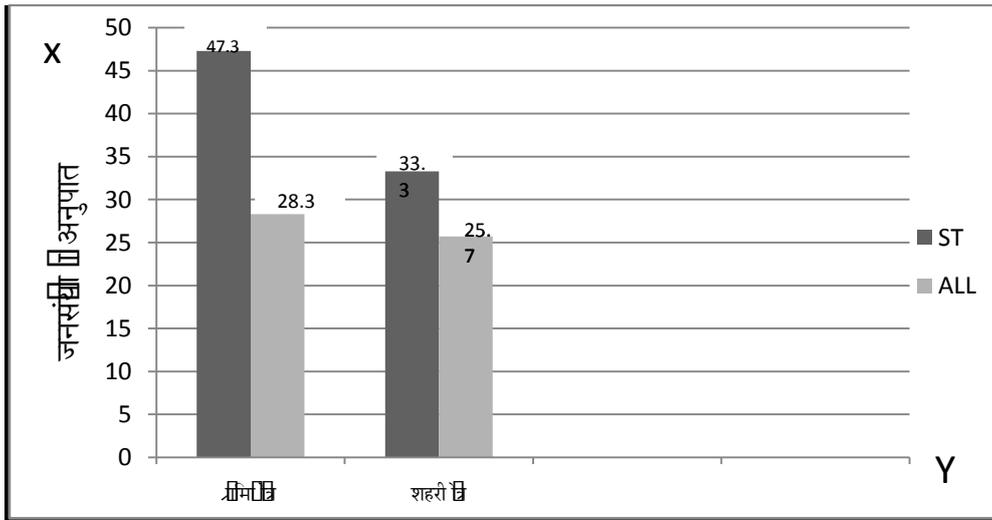
अ.क्र	मापदंड	ग्रामीण	शहरी
1.	प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कैलोरी	2400	2100
2.	प्रति व्यक्ति प्रतिमाह उपयोग व्यय	356.30	538.60

भारत के अर्थशास्त्रीयोंने या संस्थाने गरीबी उन्मूलन के लिए अपने अपने मापदंड तयार किए हैं। इन सभी का आधार 2250 कैलोरी बराबर पोषण का मुल्य है। योजना आयोगद्वारा गठित विशेषज्ञ दल (Task Force on Minimum Needs Effective Consumption Demand ) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति

2400 कैलोरी प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्राप्त न करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा के निचे माना जाता है।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा के निचे रहने वाले संपूर्ण जाती, धर्म के लोग और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या।

### गरीबी रेखा के निचे रहनेवाली जनसंख्या का अनुपात



Source :- Planning commission (2004-2005)

(Statistical profile of scheduled Tribes In India 2013 Page No. 96)

### योजना आयोग :-

2004 - 2005 के आकड़ों के अनुसार भारत में रहनेवाले विभिन्न जाती और धर्म के लोग जो संपूर्ण भारत की गरीबी रेखा के निचे रहनेवाली जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिशत 28.3 है और शहरी क्षेत्र में संपूर्ण भारत की जनसंख्या 25.7 प्रतिशत गरीबी रेखा के निचे है। और पुरी जनसंख्या में से अनुसूचित जनजाति की लाकी गरीबी रेखा के निचे रहनेवाली जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में 47.3 प्रतिशत है। और शहरी क्षेत्र में 33.3 प्रतिशत गरीबी रेखा के निचे है। अनुसूचित जनजाति में शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा गरीबी है।

भारतीय अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का विभिन्न राज्य के शहरी क्षेत्र के गरीबी का प्रतिशत (2004 - 2005)

अ.क्र	राज्य	(शहरी क्षेत्र में) अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत
1	उत्तराखण्ड	64.4
2	ओडिसा	61.8
3	कर्नाटक	58.3
4	बिहार	57.2
5	आन्ध्र प्रदेश	50.0
6	झारखण्ड	45.1
7	मध्य प्रदेश	44.7
8	छत्तीसगढ़	41.0
9	महाराष्ट्र	40.4
10	उत्तर प्रदेश	37.4
	<b>अखिल भारत</b>	<b>33.30</b>

Source :- Perspective planning Division planning commission (page - 93)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होत है कि अखिल भारत में शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की गरीबी का प्रतिशत 33.30 है। और भारत के राज्यों के शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति के निर्धनता का प्रतिशत उत्तराखण्ड में है दुसरे स्थान पर ओडीसा राज्य है जिसमे 61.8 प्रतिशत निर्धनता है। सबसे कम शहरी क्षेत्र में निर्धनता अनुपात उत्तर प्रदेश में 37.4 प्रतिशत है।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के गरीबी का प्रतिशत (2004 - 2005)

अ.क्र	राज्य	अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत (ग्रामीण क्षेत्र)
1	ओडिसा	75.6
2	मध्य प्रदेश	58.6
3	महाराष्ट्र	56.6
4	छत्तीसगढ़	54.7
5	झारखण्ड	54.2
6	बिहार	53.3
	<b>अखिल भारत</b>	<b>47.3</b>

Source :- Perspective planning Division planning commission

Statistical Profile of Scheduled Tribes In India - 2013, Page - 93

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि अखिल भारत में ग्रामीण क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति के जनसंख्या का निर्धनता 47.3 प्रतिशत है। और विभिन्न राज्यों के ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की निर्धनता सबसे ज्यादा ओडिसा में 75.6 प्रतिशत है। दुसरे स्थान पर मध्यप्रदेश है जिसकी 58.6 प्रतिशत निर्धनता अनुपात है। सबसे कम निर्धनता ग्रामीण क्षेत्र में बिहार में 53.3 प्रतिशत है।

### अनुसूचित जनजाति पर गरीबी का परिणाम

- 1) प्रति व्यक्ति आय कम हो गई है।
- 2) आर्थिक असमानता बढ़ गई है।
- 3) जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ गई है।
- 4) बेरोजगारी बड़े पैमाने में बढ़ गई है।
- 5) गरीबी के वजह से शिक्षा प्राप्त करने में बड़ी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।
- 6) गरीबी के वजह से खाना, कपडा और आवास जैसी आधारभूत आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए कई रुकावटें पैदा होती हैं। और उपभोग प्रवृत्ति कम हो गई है।
- 7) गरीबी के वजह से रहेन सहेन पर परिणाम हुआ है।
- 8) गरीबी के वजह से आदिवासीयो के स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर विपरित परिणाम हुआ।
- 9) गरीबी के वजह से आदिवासीयो के विकास पर विपरित परिणाम हुआ।

इस तरह गरीबी के वजह से भारत के अनुसूचित जनजाति पर विपरित परिणाम हुआ है।

#### संदर्भ :-

भारतीय अर्थव्यवस्था प्रतियोगिता दर्पण, 2013 - 2014

प्रियंका दत्त एवं अश्विनी महाजन, भारतीय अर्थव्यवस्था एस, चांद कंपनी लिमिटेड नई दिल्ली, 2013  
वेबसाईड

Statistical Profile of Scheduled Tribes In India, 2013, Page 93

Planning commission (2004 - 2005)